/XI/2012-56(33)2008 TC.I प्रशिक्तिओं का प्रक्रिस्टर एका जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति/ब्यय सवये

बुजेश कुमार सन्त, १२२ वर्गीयती वर्गीय होए कि विक्रीकृतिक अन्वस एवं विक्र ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन। अस्त विकास विकास विकास अस्त स्वाहित व

सेवा में; है होकड़ी कि लिंड छोड़कर्ती है कि है कि कि है कि कि है कि कि है कि कि

महाहा है गाम्य विकास, १०० कि हाति है। हाति हो है कि है। हिंदी है हिंदी है है है उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास विभाग देहरादून।

विषय:- केन्द्र सहायतित इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में योजना के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की स्वीकृति।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2793/5-लेखा-147/इ0आ0यो0-प्रस्ताव/ 2011-12 दिनांक 22.11.2011 तथा शासनादेश संख्या:1164/XI/2011-56(33)2008 TC-I के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन केन्द्र सहायतित इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में योजना के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश के रूप में कुल रू० 155.98 लाख (रूपये एक करोड़ पचपन लाख अठानवे हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने व योजना की गाइड लाइन के अनुरूप नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन उपायुक्त कार्यक्रम एवं व्यय संबंधित आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा केन्द्रॉश के आवंटन से संबंधित स्वीकृति आदेश के उपरान्त धनराशि की पुष्टि होने पर ही किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण एकमुश्त न

कर आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

2. राज्यांश की धनराशि का आवंटन नियमानुसार निर्धारित अनुपातिक आधार पर एवं संबंधित योजना हेतु नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा में किये जाने का दायित्व आपका होगा।

3. प्रश्नगत धनराशि उन्हीं कार्यों / प्रयोजनों पर ही व्यय की जायेगी जिनके लिए स्वीकृत की

जा रही है, किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।

4. प्रश्नगत योजना में निर्वतन पर रखी गयी धनराशि में से केन्द्रॉश की पूर्व स्वीकृत किश्त की धनराशि के सापेक्ष यदि राज्याँश की अवशेष देयता हो, की नियमानुसार स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर की जाय।

5. उक्त योजना की धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुरितका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति / प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6. उक्त धनराशि को आवंटित एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / मानकों व विशिष्टियों का अनुपालन

सुनिश्चित किया जाय। 7. योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु नियमानुसार दिये जा रहे अंश का व्यय इन्हीं जातियों के कल्याणार्थ कराये जा रहे कार्यों पर किया जाय।

8. स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति / व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए सूचना, स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपन्न बी०एम0—13 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

 निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग दिनॉक 31.03.2012 तक करते हुए अवशेष अप्रयुक्त धनराशि को समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10. उपरोक्त प्रस्तर—01 से 9 तक के दिशा निर्देशों में विचलन होने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

2— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—19 के अधीन लेखा शीर्षक 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम —01— समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम—800—अन्य व्यय —आयोजनागत — 01— केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें —0107— इन्दिरा आवास योजना(75% के0स0)(जिला योजना) 42—अन्य व्यय की मद से रू० 92.89 लाख, तथा अनुदान संख्या—30 के अधीन लेखाशीर्षक 2501— ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम—01— समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम—800—अन्य व्यय —02— अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—आयोजनागत— 0203— इन्दिरा आवास योजना (75% के0स0) जिला योजना—42— अन्य व्यय की मद से रू० 60.18 लाख, एवं अनुदान संख्या—31 के अधीन लेखा शीर्षक 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम — 01—समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम—आयोजनागत—796—जनजाति क्षेत्र उपयोजना —01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं—0101— इन्दिरा आवास योजना(75% के0स0) जिला योजना —42—अन्य व्यय की मद से रू० 2.91 लाख वहन किया जायेगा तथा सुसंगत इकाइयों के नाम डाला जायगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 308(P)/XXVII—4/2011

दिनांक 10 जनवरी 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय (बृजेश कुमार सन्त) अपर सचिव

संख्या ⁶ /XI/201<u>¶-56(33)2008 T.C.I तद्दिनॉक।</u> प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस, सी-1,/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
- 2. महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।

3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी निदेशक, जिलाग्राम्यविकास अभिकरण, उत्तराखण्ड।

6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।

7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।

9. निज़ी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

10. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

11. नियोजन विभाग / वित्त विभाग / समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।

12. गार्ड फाईल।

आजा से, (वीरेन्द्र प्रात्न सिंह) उप सचिव।